Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

15 - 16 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर और बिहार का तीन दिवसीय दौरा, 71,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-15 सितंबर, 2025 तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां वे 71,000 करोड़ रुपये से अधिक की बहु-क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

- **13 सितंबर को मिज़ोरम में ₹9,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें बैराबी-सैरांग रेल लाइन (₹8,070 करोड़) भी शामिल है, जो राज्य को पहली बार रेलवे से जोड़ेगी। सैरंग से दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता के लिए तीन नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।**

- **मणिपुर में, चुराचांदपुर में ₹7,300 करोड़ और इम्फाल में ₹1,200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सड़क अवसंरचना, IT हब, सिविल सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और दिल्ली व कोलकाता में नए मणिपुर भवन शामिल होंगे। वह गुवाहाटी में भूपेन हजारिका के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे।**

- **14-15 सितंबर को, PM मोदी असम में दारंग मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड और नुमालीगढ़ बायोएथेनॉल प्लांट सहित 18,530 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और बिहार में भागलपुर थर्मल प्लांट, पूर्णिया हवाई अड्डा और कोसी-मेची नदी लिंक जैसी 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।**

Key Points:-

(i) प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने, फसल-उपरांत प्रबंधन को मजबूत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे।

(ii) वे वैज्ञानिक पशु प्रजनन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन करेंगे।

(iii) प्रधानमंत्री बिहार भर में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए DAY-NRLM के तहत 500 करोड़ रुपये के सामुदायिक निवेश कोष वितरित करेंगे।

2. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पटना में APEDA क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य की कृषि-निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पटना में बिहार के पहले APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।

• उद्घाटन पटना में बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान हुआ, जिसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा उपस्थित थे।

• महिला उद्यमी नेहा आर्या के नेतृत्व में GI टैग युक्त मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन की खेप को न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए रवाना किया गया।

Key Points:-

(i) पटना APEDA कार्यालय निर्यातक पंजीकरण, सलाहकार सहायता, बाजार आसूचना, प्रमाणीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान करेगा, जिससे वाराणसी पर निर्भरता कम होगी।

(ii) बिहार के उल्लेखनीय GI-टैग उत्पादों में शाही लीची, जर्दालु आम, मिथिला मखाना और मगही पान के साथ-साथ विविध फल, सब्जियां और अनाज शामिल हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर उच्च मांग है।

(iii) APEDA ने प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों के माध्यम से बिहार के कृषि-निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है, जिसमें 22 देशों के 70 खरीदारों के साथ मई 2025 का आयोजन भी शामिल है।

3. IIT मद्रास और गाइडेंस तमिलनाडु ने भारत का पहला राज्य-स्तरीय स्टार्ट-अप डैशबोर्ड 'इनोवेशन-TN' लॉन्च किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने गाइडेंस तमिलनाडु के सहयोग से सितंबर 2025 में इनोवेशन-TN लॉन्च किया, जो तमिलनाडु में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया अपनी तरह का पहला राज्य-स्तरीय स्टार्ट-अप और इनोवेशन डैशबोर्ड है।

• इनोवेशन-TN डैशबोर्ड सूचना के लिए वन-स्टॉप स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेटर्स, निवेशकों, बैंकों और नवाचार भागीदारों की तलाश करने वाले निगमों से जोड़ता है।

• यह पहल 23 जुलाई 2025 को गाइडेंस तमिलनाडु, IIT मद्रास और YNOS वेंचर इंजन CC प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के बाद शुरू की गई है, जो राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास है।

• इस प्लेटफ़ॉर्म को IIT मद्रास स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्ट-अप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग (CREST) द्वारा IIT-इन्क्यूबेटेड YNOS वेंचर इंजन के सहयोग से विकसित किया गया है।

Key Points:-

(i) अगस्त 2025 तक, तमिलनाडु के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में 19,000 स्टार्ट-अप शामिल होंगे, जो 2.2 लाख नौकरियां पैदा करेंगे और 1.2 लाख करोड़

रुपये का निवेश आकर्षित करेंगे।

(ii) राज्य में उद्यमियों का समर्थन करने वाले 228 इनक्यूबेटर भी हैं, जिनमें से 45 स्टार्ट-अप्स ने सफलतापूर्वक 200 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं, जो तमिलनाडु के मजबूत नवाचार और वित्तपोषण वातावरण को दर्शाता है।

BANKING & FINANCE

1. भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उत्तराखंड में सतत पर्यटन के लिए 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उत्तराखंड में सतत और लचीले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

• यह परियोजना उत्तराखंड के सबसे जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक, टिहरी गढ़वाल जिले को लक्षित करेगी, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करते हुए पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है।

• इससे उन्नत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और बेहतर आपदा तैयारी प्रणालियों के माध्यम से 87,000 से अधिक निवासियों और लगभग 2.7 मिलियन वार्षिक आगंतुकों को सीधे लाभ होने की उम्मीद है।

• इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और ADB के भारत निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ के बीच हस्ताक्षर किए गए।

Key Points:-

(i) ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और वर्तमान में इसके 68 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत एक संस्थापक सदस्य है।

(ii) ADB ने 2023 में भारत के लिए 4.5 अरब डॉलर के वित्तपोषण को मंज़ूरी दी है, जिससे भारत एशिया में इसका सबसे बड़ा उधारकर्ता बन जाएगा।

(iii) उत्तराखंड भारत के घरेलू पर्यटन में लगभग 2% का योगदान देता है और इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन के साथ इको-पर्यटन को एकीकृत करना है।

2. IFC ने भारत में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन विस्तार के लिए JBM इकोलाइफ को 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया।

सितंबर 2025 में, विश्व बैंक समूह (WBG) की निजी क्षेत्र की शाखा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने भारत भर में इलेक्ट्रिक बसों और अभिनव शहरी गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए JBM ऑटो लिमिटेड की सहायक कंपनी JBM ECOLIFE (JBM) को 137

मिलियन अमेरिकी डॉलर (1,210 करोड़ रुपये) देने का वादा किया। यह IFC का सबसे बड़ा वैश्विक ई-बस निवेश और एशिया में पहला निवेश है।

• IFC की फंडिंग को JBM ECOLIFE के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (883 करोड़ रुपये) और एवरसोर्स कैपिटल द्वारा समर्थित ग्रीनसेल के लिए 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर (327 करोड़ रुपये) में विभाजित किया गया है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल का समर्थन करता है।

• इस परियोजना के तहत 8 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों: महाराष्ट्र, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली की 39 नगर पालिकाओं में 4,000 ई-बसें और संबंधित चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

• इस पहल में नगरपालिका और राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए भुगतान जोखिम को कम करने, देश भर में ई-बस परियोजनाओं की बैंकिंग क्षमता और प्रतिकृति में सुधार करने के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) को शामिल किया गया है।

Key Points:-

(i) भारत में वर्तमान में 2 मिलियन से अधिक बसें संचालित होती हैं, और सरकार ने वित्त वर्ष 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक बसों के प्रवेश का लक्ष्य रखा है, जो टिकाऊ शहरी परिवहन विकास पर जोर देता है।

(ii) IFC का निवेश वैश्विक ई-मोबिलिटी वित्तपोषण में एक मील का पत्थर है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा ई-बस वित्तपोषण बनाता है और इस क्षेत्र में IFC द्वारा पहला एशियाई उद्यम है।

ECONOMY & BUSINESS

1. ICRA ने GST में भारी कटौती के बाद वित्त वर्ष 2025 की GDP वृद्धि दर को संशोधित कर 6.5% कर दिया, बैंक और NBFC ऋण मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया।

रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि के अपने पूर्व अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि इस सुधार का श्रेय GST दरों में तेज और अप्रत्याशित कटौती को दिया गया है, साथ ही पहले दी गई आयकर राहत को भी, जिससे घरों में 3 लाख करोड़ रुपये आए हैं, जिससे उपभोग और ऋण वृद्धि की संभावनाएं बढ़ी हैं।

• ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आयकर राहत के साथ-साथ जीएसटी कटौती के त्वरित कार्यान्वयन ने वित्त वर्ष 2025 के GDP विकास पूर्वानुमान को घटाकर 6% से 6.5% कर दिया है, जो पहले के नकारात्मक दृष्टिकोण को उलट देता है।

• बैंकों के संबंध में, ICRA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उच्च प्रयोज्य आय से खुदरा ऋण की मांग बढ़ेगी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनी रहेगी, तथा यदि उपभोग में और वृद्धि होती है तो संभवतः कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

• NBFCs के लिए, ICRA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष AM कार्तिक ने कहा कि उपभोग-आधारित मांग में वृद्धि से असुरक्षित और माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो में जोखिम कम होगा, जबकि संतुलित ऋण वृद्धि मिश्रण के लिए वाहन और आवास जैसे क्षेत्रों को समर्थन मिलेगा।

Key Points:-

(i) वृद्धिशील बैंक ऋण वित्त वर्ष 2025 में 18 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 19-20.5 लाख करोड़ रुपये (10.4-11.3% वृद्धि) होने का अनुमान है, जबकि इन्फ्रा-केंद्रित संस्थाओं को छोड़कर एनबीएफसी ऋण में 15-17% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 17% थी।

(ii) हालांकि वृद्धिशील बैंक ऋण एक वर्ष पूर्व के 5.1 लाख करोड़ रुपये से घटकर अप्रैल-अगस्त वित्त वर्ष 26 में 3.9 लाख करोड़ रुपये रह गया, लेकिन ICRA को उम्मीद है कि GST युक्तिकरण और CRR में कटौती से मांग में और तेजी आएगी, जिसे पर्याप्त तरलता और ऋण-से-जमा अनुपात में आसानी से मदद मिलेगी।

(iii) MSMEs और असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण (184 लाख करोड़ रुपये के गैर-खाद्य बैंक ऋण का 17%) और छोटे NBFC(35 लाख करोड़ रुपये का 34%) के लिए ऋण कमजोरियां बनी हुई हैं, जिसमें बैंकों के लिए अनुमानित ऋण लागत ~ 13 bps और NBFCs के लिए ~ 30 bps बढ़ रही है, विशेष रूप से गैर-आवासीय क्षेत्रों में।

2. भारत फोर्ज ने भारत में स्वायत्त कार्गो ड्रोन की तैनाती के लिए UK की विंडरेसर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सितंबर 2025 में, भारत फोर्ज, एक अग्रणी फोर्जिंग और उन्नत इंजीनियरिंग कंपनी, ने भारत भर में UAV अल्ट्रा की तैनाती के लिए UK स्थित विंडरेसर्स, एक स्वायत्त कार्गो ड्रोन निर्माता के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- **समझौता ज्ञापन की प्रारंभिक अवधि दो वर्ष है, जिससे दोनों कंपनियां स्थानीयकरण, संयुक्त परीक्षण और भारत के लिए एक निश्चित तैनाती योजना तैयार करने में सक्षम होंगी।**

- **अल्ट्रा ड्रोन से भारत के सैन्य और नागरिक क्षेत्रों को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए कैरियर ऑन बोर्ड डिलीवरी (COD) और भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए महत्वपूर्ण रसद सहायता शामिल है।**

- **यह सहयोग यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और विजन 2035 के अनुरूप है, जो दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा देगा।**

Key Points:-

(i) इस समझौता ज्ञापन पर लंदन, यूके में आयोजित रक्षा एवं सुरक्षा उपकरण अंतर्राष्ट्रीय (DSEI) 2025 प्रदर्शनी में हस्ताक्षर किए गए।

(ii) भारत फोर्ज-विंड्रेसर्स साझेदारी भारत की स्वायत्त हवाई प्रणालियों को आगे बढ़ाती है, तथा सशस्त्र बलों

के लिए रसद और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाती है।

(iii) अल्ट्रा UAV नौसेना, सेना और वायु सेना के लिए सटीक कार्गो डिलीवरी, दीर्घकालिक मिशन और कुशल संचालन को सक्षम बनाता है, साथ ही नागरिक परिवहन आवश्यकताओं का भी समर्थन करता है।

MOUs and Agreement

1. TCS और C-DAC ने भारत के सॉवरेन क्लाउड इकोसिस्टम के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सितंबर 2025 में, टाटा समूह की प्रमुख IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भारत के संप्रभु क्लाउड पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास निकाय, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- **समझौता ज्ञापन AI-सक्षम संप्रभु क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाने पर केंद्रित है जो स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और शासन में सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करते हुए भारत के डेटा स्थानीयकरण नियमों का अनुपालन करता है।**

- **इस सहयोग का उद्देश्य ओपनस्टैक फ्रेमवर्क का लाभ उठाकर और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके वैश्विक हाइपरस्केलर्स पर निर्भरता को कम करना है, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।**

- **e-Sanjeevani (टेलीमेडिसिन सेवा) और डायल 112 (राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन) जैसे प्रमुख सरकारी अनुप्रयोगों को TCS के सॉवरेनसिक्योर क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा, जिससे सख्त राष्ट्रीय डेटा संरक्षण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।**

Key Points:-

(i) C-DAC की स्थापना 1988 में हुई थी और यह उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC), क्लाउड और AI-संचालित प्रौद्योगिकियों में भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है।

(ii) TCS का सॉवरेनसिक्योर क्लाउड एक सरकारी स्तर का प्लेटफॉर्म है जिसमें एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और AI-आधारित निगरानी है।

(iii) यह समझौता ज्ञापन शासन और सेवाओं के लिए सुरक्षित स्वदेशी डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करके डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2015) का समर्थन करता है।

2. NCSSR और IIT-दिल्ली ने खेल विज्ञान और स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र (NCSSR) ने हाल ही में खेल विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और स्वदेशी नवाचार में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (IIT-D) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

• समझौता ज्ञापन पर IIT-दिल्ली परिसर में डॉ. बिभु कल्याण नायक (NCSSR) और प्रोफेसर के. अग्रवाल (IIT-D) द्वारा युवा मामले एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव और IIT-D के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

• यह सहयोग एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार, चोट की रोकथाम और वैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही शीर्ष वैज्ञानिकों और खेल संस्थानों के बीच ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देगा।

• IIT-दिल्ली में एक नई बायोमैकेनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, जो उन्नत खेल विज्ञान मूल्यांकन करने और एथलीटों के प्रदर्शन और कल्याण के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए सुसज्जित है।

Key Points:-

(i) NCSSR की स्थापना 2017 में SAI के उच्च प्रदर्शन केंद्रों के तहत कुलीन एथलीटों के लिए चिकित्सा, खेल और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को एकीकृत करने के लिए की गई थी।

(ii) IIT-दिल्ली स्थित बायोमैकेनिक्स प्रयोगशाला को मोशन-कैप्चर सिस्टम, फोर्स प्लेट्स और पहनने योग्य सेंसर के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे वास्तविक समय में बायोमैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल विश्लेषण संभव हो सकेगा।

(iii) यह समझौता ज्ञापन भारत के 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी के रोडमैप का भी समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए स्वदेशी वैज्ञानिक प्रशिक्षण मॉडल बनाना है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. सी.पी. राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।

11 सितंबर 2025 को, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रपुरम पोन्नुसामी (सी.पी.) राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव के बाद इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का अतिरिक्त निर्वहन करने के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को नियुक्त किया।

• आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका के अलावा लघु रूप से महाराष्ट्र के राज्यपाल एसोसिएटेड वर्क की झलक दिखाएंगे,

जिससे राज्य में संवैधानिक पद की तटस्थता बनी रहेगी।

• सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया, इस पद पर वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

Key Points:-

(i) आचार्य देवव्रत, एक राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद्, ने 35 से अधिक वर्षों तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित एक गुरुकुल के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया और वैदिक मूल्यों, सामाजिक सुधारों और शिक्षा को बढ़ावा दिया।

(ii) उन्होंने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (अगस्त 2015-जुलाई 2019), 22 जुलाई 2019 से गुजरात के राज्यपाल, और गुजरात विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय और गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति।

(iii) संवैधानिक रूप से, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 155), राष्ट्रपति की इच्छा पर 5 वर्ष तक कार्य करता है (अनुच्छेद 156), और राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ लेता है (अनुच्छेद 159); उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा किया जाता है (अनुच्छेद 66), वह 5 वर्ष तक कार्य करता है (अनुच्छेद 67), और राष्ट्रपति से शपथ लेता है (अनुच्छेद 69)।

2. FSIB ने SBI के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में रवि रंजन की सिफारिश की और ACC से अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

सितंबर 2025 में, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के उप प्रबंध निदेशक (DMD) रवि रंजन को प्रबंध निदेशक (MD) के पद के लिए अनुशंसित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) अंतिम निर्णय लेगी। यदि नियुक्त होते हैं, तो वह विनय एम. टोंस का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।

• वर्तमान में SBI का नेतृत्व एक अध्यक्ष (चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी) और चार MDs कर रहे हैं, जिनमें अश्विनी कुमार तिवारी, विनय एम टोंस, राणा आशुतोष कुमार सिंह और राम मोहन राव अमारा शामिल हैं।

• FSIB की सिफारिश के अनुसार SBI के MD की नियुक्ति को औपचारिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ACC की मंजूरी की आवश्यकता है।

Key Points:-

(i) रवि रंजन SBI में ग्लोबल मार्केट्स के लिए DMD हैं, जिनके पास 33 वर्षों से अधिक का बैंकिंग अनुभव है, वे 1991 में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के रूप में शामिल हुए थे।

(ii) उन्होंने SBI में प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें चेन्नई सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक (CGM), SBI सिंगापुर में उपाध्यक्ष, SBI की विदेशी शाखाओं में उप महाप्रबंधक (DGM) और मुंबई में SBI के

कॉर्पोरेट सेंटर में परियोजना वित्त और लीजिंग में महाप्रबंधक (GM) शामिल हैं।

(iii) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के अंतर्गत जुलाई 2022 में स्थापित FSIB, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (PSIC) और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और कार्यकारी निदेशक (WTD) की नियुक्तियों की सिफ़ारिश करता है। इसके अध्यक्ष पूर्व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) सचिव भानु प्रताप शर्मा हैं।

App and Web Portal

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम मिशन और पोर्टल लॉन्च किया।

सितंबर 2025 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम मिशन और इसके समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसमें पांडुलिपि डिजिटलीकरण और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया।

• प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास में करोड़ों पांडुलिपियों के नष्ट होने के बावजूद भारत के पास लगभग एक करोड़ पांडुलिपियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जो ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति देश की सभ्यतागत निष्ठा को रेखांकित करता है।

• उन्होंने कहा कि वैश्विक सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का मूल्य 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, और डिजिटल पांडुलिपियां दुनिया भर में नवाचार, अनुसंधान और सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल डेटाबैंक के रूप में कार्य कर सकती हैं।

• तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका विषय था "पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना", विद्वानों, प्रौद्योगिकीविदों, संरक्षणवादियों और नीति विशेषज्ञों को पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करने और वैश्विक ज्ञान संवाद को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया।

Key Points:-

(i) ज्ञान भारतम् पोर्टल पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुँच के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा।

(ii) यह मिशन भारत के प्राचीन ज्ञान को वैश्विक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल संग्रह और क्लाउड टूल्स के माध्यम से युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है।

(iii) सम्मेलन में दुर्लभ पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया गया और कानूनी ढाँचे, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपि के अर्थ-निर्धारण पर चर्चा की गई।

IMPORTANT DAYS

1. भारत ने वन संरक्षकों के सम्मान में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया।

11 सितंबर, 2025 को भारत राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाएगा, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के साथ वनों, पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के बलिदान को याद किया जाएगा।

- **11 सितंबर 1730 को, अमृता देवी बिश्नोई और उनकी बेटियों के नेतृत्व में 363 से अधिक बिश्नोई ग्रामीणों ने महाराजा अभय सिंह के अधिकारियों के आदेश पर पवित्र खेजड़ी के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए राजस्थान के खेजरली में अपने प्राणों की आहुति दी थी।**

- **खेजरली नरसंहार को भारत में पर्यावरण-नारीवाद और पर्यावरण विरोध के शुरुआती कृत्यों में से एक माना जाता है, जहां महिलाओं ने जैव विविधता और वन अधिकारों की रक्षा में नेतृत्व किया था।**

- **1982-83 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया खेजड़ी वृक्ष (प्रोसोपिस सिनेरिया) अपनी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका के कारण "थार रेगिस्तान का कल्पवृक्ष" के रूप में जाना जाता है, जो राजस्थान के दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है और शुष्क क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक जीवन में सहायता करता है।**

Key Points:-

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2013 में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में घोषित किया। मुख्य समारोह प्रतिवर्ष उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय वन शहीद स्मारक पर आयोजित किया जाता है।

(ii) 1988 में, डाक विभाग ने खेजड़ी वृक्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिसमें इसके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य पर प्रकाश डाला गया। खेजड़ी नरसंहार ने बाद में उत्तराखंड के चमोली में चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन (1973) को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी जंगलों में हरे पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया।

(iii) भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR 2023) के अनुसार, भारत का वन आवरण उसके भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, जबकि कुल वन और वृक्ष आवरण संयुक्त रूप से 25.17% है, जो ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन भंडारण और वर्षा विनियमन में "पृथ्वी के फेफड़ों" के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

2. संयुक्त राष्ट्र ने 12 सितंबर, 2025 को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस मनाता है।

• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 23 दिसंबर 2003 को प्रस्ताव A/RES/58/220 को अपनाया, जिसके तहत 19 दिसंबर को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसका पहला आयोजन 2004 में किया गया।

• 2011 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग (TCDC) के लिए 1978 ब्यूनस आयर्स कार्य योजना (BAPA) के उपलक्ष्य में इस दिवस को 12 सितम्बर को स्थानांतरित कर दिया।

• संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय (UNOSSC) की स्थापना 1974 में विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए UNDP के भीतर एक विशेष इकाई के रूप में की गई थी, जिसे बाद में 2013 में UNOSSC के रूप में पुनर्गठित किया गया।

Key Points:-

(i) 2025 का विषय है "दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से नए अवसर और नवाचार", जिसमें प्रतिबद्धताओं और समावेशिता पर कार्रवाई पर जोर दिया गया है ताकि कोई भी देश पीछे न छूटे।

(ii) UNOSSC, UNGA और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर उच्च स्तरीय समिति (HLCSSC) के मार्गदर्शन में कार्य करता है, तथा वैश्विक स्तर पर दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) को सुविधाजनक बनाता है।

(iii) दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के बीच एकजुटता को मजबूत करता है, जिससे व्यापार, नवाचार, क्षमता निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय साझेदारी संभव होती है।

DEFENCE

1. राजनाथ सिंह ने विश्व की पहली त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन यात्रा 'समुद्र प्रदक्षिणा' को हरी झंडी दिखाई।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र से दुनिया के पहले त्रि-सेवा सभी-महिला जलयात्रा नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।

• इस अभियान का नेतृत्व भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की 10 महिला अधिकारी कर रही हैं, जिससे यह तीनों सेनाओं के किसी महिला दल द्वारा दुनिया भर में नौकायन का पहला प्रयास है। वे पुडुचेरी में निर्मित स्वदेशी 50 फुट लंबी क्लास ए नौका, IASV त्रिवेणी पर सवार होकर यात्रा करेंगी।

• अपनी यात्रा के दौरान, चालक दल भूमध्य रेखा को दो बार पार करेगा और तीन महान अंतरीपों - ऑस्ट्रेलिया में केप लीउविन, दक्षिण अमेरिका में केप हॉर्न और दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ़ गुड होप - से होकर गुज़रेगा। सबसे कठिन चरण दक्षिणी महासागर और ड्रेक पैसेज होगा।

• वैश्विक यात्रा में चार अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह शामिल होंगे - फ्रेमेंटल (ऑस्ट्रेलिया), लिटलटन (न्यूजीलैंड), पोर्ट स्टेनली (कनाडा) और केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका)।

Key Points:-

(i) इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय जलयात्रा मानक का पालन करते हुए लगभग 21,600 समुद्री मील (40,000 किमी) की दूरी तय करने की योजना है।

(ii) महिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भारतीय सेना एडवेंचर विंग (IAAW) के तहत आयोजित किया गया और अनुभवी नौसेना नौकायन प्रशिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण किया गया।

(iii) यह पहल भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती के 75वें वर्ष (1949 से) के साथ संरेखित है, जो इसे सैन्य लिंग समावेशन में एक ऐतिहासिक घटना बनाती है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. इंद्रा और TASL ने INS मैसूर पर भारत का पहला स्वदेशी 3D वायु निगरानी रडार 'लांज़ा-एन' स्थापित किया।

10 सितंबर 2025 को, इंद्रा (स्पेन) और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने भारत के पहले स्वदेशी त्रि-आयामी वायु निगरानी रडार (3D-ASR) लांज़ा-एन को INS मैसूर पर भारतीय नौसेना को सफलतापूर्वक सौंप दिया और उसे चालू कर दिया। यह स्पेन के बाहर इस रडार की पहली तैनाती है।

• लांज़ा-एन रडार ड्रोन, सुपरसोनिक विमान, नौसैनिक प्लेटफ़ॉर्म और विकिरण-रोधी मिसाइलों सहित कई खतरों का पता लगाकर भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा और मिसाइल-रोधी क्षमताओं को बढ़ाता है।

• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम (TTP) के तहत 2020 में हुए एक अनुबंध के तहत 2029 तक 23 नौसैनिक रडारों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिसमें इंद्रा 3 की आपूर्ति करेगी और TASL अपने कर्नाटक संयंत्र में 20 का निर्माण करेगी।

• TASL ने उत्पादन और भविष्य की नौसेना तैनाती में सहायता के लिए कर्नाटक में एक समर्पित रडार संयोजन, एकीकरण और परीक्षण सुविधा स्थापित की है।

Key Points:-

(i) लांज़ा-एन दूरी, दिशा और ऊँचाई मापकर 3D पहचान प्रदान करता है, और व्यापक निगरानी के लिए इसकी सीमा 256 समुद्री मील (~474 किमी) तक है।

(ii) इस रडार को भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित किया गया है, जो अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता में काम करने में सक्षम है, जिससे विविध वातावरणों में विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

(iii) यह ऑनबोर्ड नौसेना प्रणालियों के साथ पूरी तरह से एकीकृत है और नौसेना और हवाई प्लेटफार्मों पर कठोर परीक्षणों में सफल रहा है, जिससे युद्ध की तैयारी सुनिश्चित होती है।

ENVIRONMENT

1. असम के वन विभाग के नाम पर नई छिपकली प्रजाति 'सिर्टोडासिलस वनरक्षक' का नाम रखा गया।

सितंबर 2025 में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दीमा हसाओ जिले के पर्वतीय जंगलों में एक नई मुड़ी हुई पंजों वाली छिपकली, सिर्टोडासिलस वनरक्षक की खोज की घोषणा की।

- **वन संरक्षण में इसकी भूमिका को मान्यता देते हुए, इस प्रजाति का नाम असम के वन विभाग के नाम पर रखा गया है।**
- **इस खोज के साथ ही असम में पाई जाने वाली सिर्टोडासिलस प्रजातियों की कुल संख्या बढ़कर पाँच हो गई है।**
- **यह खोज मन्मथ भराली, मथिपी वबेइरियुरेइलई और रूपांकर भट्टाचार्य सहित शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा जर्नल ऑफ एशिया-पैसिफिक बायोडायवर्सिटी में प्रकाशित की गई थी।**

Key Points:-

(i) वनरक्षक नाम संस्कृत शब्दों वन (वन) और रक्षक (रक्षक) से आया है, जो संरक्षण का प्रतीक है।

(ii) यह प्रजाति साइरटोडैक्टाइलस खासिएन्सिस समूह से संबंधित है, जो पूर्वोत्तर भारत में उच्च स्थानिकता और सीमित वितरण के लिए जानी जाती है।

(iii) यह खोज असम के पर्वतीय वनों की जैव विविधता के महत्व को उजागर करती है, जहाँ दुर्लभ और स्थानिक सरीसृप जीव पाए जाते हैं।

2. पश्चिमी घाट में नई काली फफूंद प्रजातियां एस्परगिलस ढाकेफाल्करी और एस्परगिलस पेट्रीसियाविलशायरी खोजी गईं।

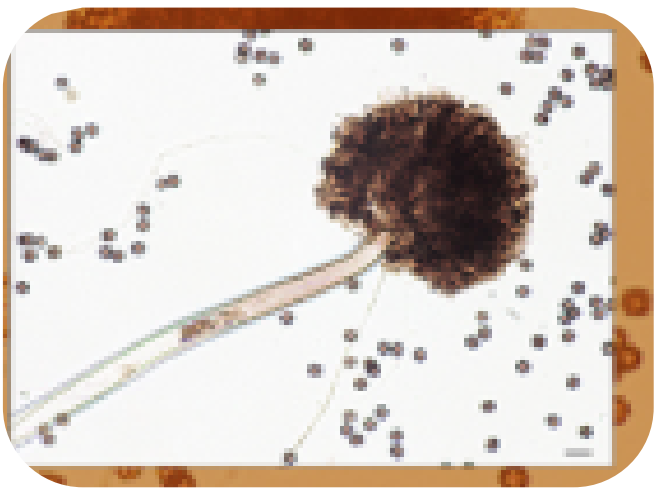

सितंबर 2025 में, महाराष्ट्र के पुणे स्थित MACS-अघारकर अनुसंधान संस्थान (ARI) के शोधकर्ताओं ने UNESCO जैव विविधता हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट के मिट्टी के नमूनों से दो नई काली एस्परगिलस प्रजातियों - एस्परगिलस ढाकेफाल्करी और एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्सशायरी - की खोज की।

- **इस खोज ने पश्चिमी घाट में एस्परगिलस एक्यूलेटिनस और एस्परगिलस ब्रुनेओविओलेसियस के पहले भौगोलिक रिकॉर्ड को भी चिह्नित किया।**
- **नई प्रजातियाँ विशिष्ट रूपात्मक विशेषताओं जैसे पीले रंग के स्केलेरोशिया, काँटेदार कोनिडिया और शाखाओं वाले कोनिडियोफोरस प्रदर्शित करती हैं।**
- **निष्कर्ष पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक समृद्धि और वैज्ञानिक एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के**

लिए कवक जैव विविधता का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं।

Key Points:-

(i) एस्परगिलस ढाकेफाल्करी हल्के से गहरे भूरे रंग के बीजाणुओं, एक-सीरीएट कोनिडियोफोरस (2-3 शाखाएं) और चिकनी दीर्घवृत्ताकार कोनिडिया के साथ तेजी से बढ़ने वाली कॉलोनियां बनाता है।

(ii) एस्परगिलस पेट्रीसियाविलशायरी तीव्र वृद्धि, प्रचुर मात्रा में पीले-नारंगी स्केलेरोशिया, तथा विशिष्ट माध्यम पर अम्ल उत्पादन दर्शाता है, जिसमें कोनिडियोफोर पांच या अधिक स्तंभों में शाखाएं बनाते हैं।

(iii) अध्ययन में प्रजातियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए आंतरिक ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर (ITS), कैल्मोडुलिन (CaM), बेनए और RPB2 जीन जैसे आणविक मार्करों का उपयोग किया गया, जिससे इसकी व्यवस्थित और वर्गीकरण संबंधी महत्ता पर प्रकाश डाला गया।

Static GK

Indian Army (IA)	सेना प्रमुख (COAS) जनरल उपेंद्र द्विवेदी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Tata Consultancy Services (TCS)	CEO : के. कृतिवासन	मुख्यालय: मुंबई
Sports Authority of India (SAI)	महानिदेशक (DG) : हरि रंजन राव	मुख्यालय: नई दिल्ली
Asian Development Bank	अध्यक्ष: मसाटो कांडा	मुख्यालय: मंडलुयोंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस
Bihar	राजधानी: पटना	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार
ICRA Limited	CEO : रामनाथ कृष्णन	स्थापना: 1991
Maharashtra	मुख्यमंत्री (CM) : देवेंद्र फडणवीस	राजधानी : मुंबई
Agharkar Research Institute (ARI)	निदेशक : डॉ. प्रशांत धाकेफालकर	मुख्यालय : णे, महाराष्ट्र
United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC)	निदेशक : दीमा अल-खतीब	मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
Tamil Nadu	मुख्यमंत्री: एम के स्टालिन	राज्यपाल: आर. एन. रवि